(e) In Maharashtra 266 Watershed projects have been sanctioned by the State Level Sanctioning Committee

(f) In accordance with the Project Guidelines one Model Watershed in each of the Agro-climatic Zones is finalised by Government of India in consultation with the officials of the State Governments, which are then put up for consideration and approval of National Watershed Development Policy Committee.

Based on the Approved Model Watershed Projects, the State Level Sanctioning Committee approves the other Watersheds projects.

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की उपलब्धियां

4425. **श्री कामेश्वर पासवान :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की पिछले दो वर्षों की क्या उपलब्धियां हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अनुसंधान पर किया गया खर्च कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि देने में असफल रहा है;

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन प्रकाशन और सूचना प्रभाग स्थापित किये जाने के क्या उद्देश्य है और यह अपने उद्देश्य में कितना सफल रहा है ;

(घ) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण अनुसंधान कार्य में भारी गिरावट आयी है ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि प्रकाशन प्रभाग की पत्रिकायें इसके पाठकों को तीन-चार महीने बाद मिल पाती हैं; और

(च) यदि हां, तो इन प्रकाशनों के अत्यधिक विलंब से आने के क्या कारण हैं?

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) विभिन्न फसलों के अधिक उपज देने वाली किस्मों/संकरों को रिलीज किया गया/पता लगाया गया । इससे खाद्यान्न की 192, तिहलनों की 74, दलहनी फसलों की 21, व्यावसायिक फसलों की 30 और चारे वाली फसलों की 16 किस्में/संकर शामिल हैं । आगे ब्यौरा विवरण के रूप में दिया जा रहा है । **(नीचे देखिये)**

(ख) जी, नहीं । यह तथ्य नहीं है । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बारानी और सिंचित पारिस्थितियों दोनों स्थितियों के लिये अधिक उपज देने वाली, खाद्यान्न, दहलनी, तिलहनी और बागवानी फसलों की अधिक उपज देने वाली तैयार की गयी किस्मों के रूप में महत्वपूर्ण परिणाम दिखाये ।

(ग) प्रकाशन एवं सूचना प्रभाग की स्थापना भा0कृ0अ0प0 के इस कार्यदेश का पालन करने के लिये हुई थी जिसमें "परिषद को न केवल अनुसंधान बल्कि सामाय रूप से कृषि और पशु चिकित्सा संबंधी मामलों के संबंध में प्राप्त सूचनाओं के क्लीयरिंग हाउस (सूचना प्राप्त करना व वितरित करना) के रूप में कार्य करना है । प्रभाग प्रारंभ से ही अंग्रजी और हिन्दी में नियमित रूप से पत्रिकायें और विभिन्न अंगों पर 1000 से अधिक गैर-आवधिक प्रकाशन प्रकाशित करके काफी हद तक इस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है । इनमें से कुछ प्रकाशनों की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है और इनसे परिषद को काफी ख्याति मिली है । प्रभाग ने एफ.ए.ओ. और साक के स्तर पर राष्ट्रीय सूचना में भी अंशदान दिया है और अन्तर्राष्ट्रीय सूचना-तंत्रों जैसे एग्रिस, सी.ए.आर.आई.एस. और एस.ए.आई.सी को समृद्ध किया है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) जी, नहीं । यह तत्थयात्मक सत्य नहीं है ।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

भा० कृ० अनु० परिषद की संक्षिप्त उपलब्धियां

विभिन्न फसलों की अधिक पैदावार वाली किस्मों/संकरों को जारी करना। इनमें 192 अनाज की, 74 तिलहन की, 21, दालों की, 30 व्यावसायिक फसलों और 16 चारे की फसलें जारी की गई । उनका पता लगाया गया ।

अधिक तेजी से बढ़ने वाली तथा जल्द तैयार होने वाली धान की किस्मों का विकास । ये किस्में नमी की कमी को काफी हद तक बर्दास्त कर लेती हैं तथा बारानी नीची भूमि के लिये उपयुक्त हैं तथा अधिक पैदावार भी देती हैं (रिनिधन, सावित्री, गायत्री और तुलसी) ।

तिलहनों (28023 क्विंटल), दालों (14603 क्वि०), अनाज (26040 क्वि०), और मोटे अनाज (1242 क्वि०) के प्रजनक बीजों के उत्पादन में वृद्धि ।

"एल.आर.ए. 5156" कपास की एक नई किस्म का विकास ।

बागानी फसल की 33 उन्नत कल्टीवर्स/संकरों का विकास जिसमें ये शामिल हैं:—आम के श्रेष्ठ दसहरी क्लोन और आम के संकर 117, अनार की संकर किस्म, आंवला की दो सख्त किस्में, सब्जियों की 10 किस्में, गंगा-सिंधु के मैदान के लिये आलू की एक संकर किस्म, आंध्र प्रदेश के लिये शकरकन्दी का कल्टीवर, दो काजू के कल्टीवर्स, मसाले और औषधीय पौधों की 12 किस्में ।

बिना उत्पादन में कमी किये 30 प्रतिशत जल की बचत के लिये नई और अधिक कारगर सस्य पद्धति का विकास करना ।

305 दिनों के दुग्धकाल के दौरान 2,790 किलो० दूध देने वाली श्रेष्ठ भैंसों के एक झुंड को तैयार करना ।

अंडे वाली मुर्गियों को रिलीज करना जो 6 सप्ताह में 1400 ग्राम से अधिक शरीर भार को प्राप्त कर लेती है और जिनकी मत्युदर भी कम हो ।

मछली के तलाबों की उत्पादकता की 50 किलो/हेक्टे०/वर्ष से बढ़ाकर 1850 किलो/हैक्ट०/वर्ष करने के लिये प्रौद्योगिकी का विकास करना । इसी तरह जलाशयों की उत्पादन क्षमता 20 से बढ़ाकर 220 किलो०/हैक्ट०/वर्ष करना ।

दीर्घ अवधि तक दूध के भंडारण के लिये नई टेक्नोलाजी का विकास करना।

अधिकांश कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों में 4,000 प्रदर्शन किये गये इनमें चावल, दालों तथा तिलहनों की फसलों पर प्रदर्शन किये गये । इससे यह प्रदर्शित हुआ कि पास के खेत से प्रदर्शन वाले खेतों में फसल दो से तीन गुनी प्राप्त की गई ।

प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम विशेषकर बारानी कृषि के क्षेत्रों में 20,000 किसान परिवारों को अपनाया गया जिसमें 40 प्रतिशत उत्पादकता बढ़ी ।

कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा 9516 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये जिससे 2,07,446 प्रशिक्षार्थियों तथा 1445 प्रशिक्षकों को लाभ पहुंचा ।

26,500 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति किसान परिवारों की उनके आर्थिक उत्थान के लिये तैयार प्रायोजनाओं के जरिये वार्षिक आय रु० 1000 से 3000 तक बढ़ गयी ।

देश में 180 जिलों में 183 कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किये गये हैं ।

संसद में एक विधेयक पारित किया गया था तथा केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई जिसमें विभिन्न उत्तर पूर्वी राज्यों में छः महाविद्यालय हैं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न शाखाओं में 15 नयी योजनाओं जैसे एक संस्थान, 7 राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, 2 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना, 1 नेटवर्क तथा 4 अन्य योजनाओं (शिक्षक योजनाएं) का प्रस्ताव रखा गया है।

जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय को आवंटित धनराशि

4426. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय को चारा उत्पादन हेतु कितनी धनराशि आवंटित की है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कितने मूल्य के चारे का उत्पादन किया गया;

(ग) उपर्युक्त विश्वविद्यालय द्वारा उत्पादित चारे का उपयोग कौन करता है ; और

(घ) क्या चारा उत्पादन इकाई में बीज उत्पादन की भी अनुमति दी गई है और क्या ये बीज किसानों को उपलब्ध कराये जाते हैं ?

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री एस. कृष्ण कुमार): (क) से (घ) जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से सूचनाएं एकत्रित की जा रही है।

सूखे से प्रभावित लोगों को सहायता देना बन्द किया जाना

4427. **श्री कामेश्वर पासवान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नलकूप/बांस बोरिंग, सिंचाई कूप और "डग वैल" के निर्माता तथा पम्प सेटों के वितरण जैसे किसानोपयोगी कार्यक्रम के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली 50 प्रतिशत की वित्तीय सहायता इस वर्ष बन्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो इस वर्ष दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त सहायता बंद कर देने से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसान, सीमान्त किसान और छोटे किसान प्रभावित होंगे जिन्हें क्रमशः शत प्रतिशत, दस प्रतिशत और पचहत्तर प्रतिशत राज-सहायता स्वीकार्य है ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) उथले नलकूप/खुदे हुए कुओं के निर्माण के लिये छोटे और सीमांत किसानों को सहायता देने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना, राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्णय के अनुसार पहली अप्रैल, 1992 से राज्यों को हस्तांतरित कर दी गई थी तथा धन भी उसी वर्ष संबंधित राज्यों को हस्तांतरित कर दिया गया था।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

4428. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की